MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will get it examined and see whether it is done under the rules. ...*(Interruptions)*... I will get it examined.

**202. [The questioner (Prof. M. M. Agarwal) was absent. For answer vide page 47]*

Registered units of SSIs in the country

*203. SHRI MATILAL SARKAR: Will the Minister of SMALL SCALE INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the number of registered units of small scale industries in the country upto the 31st December, 2005, State-wise and Union Territory-wise;

(b) how many of these are in running condition and how many have been closed;

(c) the reasons for such a big number of units having been closed;

(d) the number of workers having lost their work; and

(e) the steps taken to check failures upto such an extent?

THE MINISTER OF SMALL SCALE INDUSTRIES (SHRI MAHAVIR PRASAD): (a) to (e) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) According to the information received from the Directorates of Industries of States/Union Territories, the estimated total number of SSI units registered all over the country upto 31 December 2005 was 18,41,248. The State-wise and Union Territory-wise break-up of these registered small scale industries is given in the enclosed Statement-I (*see* below).

(b) The information on closed small scale industries has not been collected by the State Governments/Union Territory Administrations or the Central Government after the Third All India Census (2002-03) of small scale industries. According to the results of that Census, 39 per cent of small scale industries registered upto 31 March 2001 were found closed during enumeration.

(c) Fall in demand for the products of SSI units, use of outdated technology, difficulty in availability of working capital and raw materials, constraints in electricity supply and other infrastructure, management inadequacies, etc., are some of the main reasons of closure of these units.

(d) The data on the number of workers rendered jobless due to closure of SSIs are not maintained at the Central level.

(e) The respective State Governments and the Union Territory Administrations are primarily responsible for the promotion and development of SSIs. However, several policy decisions have been taken and several schemes/programmes are implemented by the Central Government for the development and promotion of SSI. Among them, ensuring availability of credit through public sector financial institutions (including banks), technology upgradation, marketing assistance, integrated infrastructural development, etc., are important.

The Government has announced a "Policy Package for Stepping up of Credit to Small and Medium Enterprises" on 10 August 2005. Based on this, the Reserve Bank of India has issued detailed guidelines to the banks regarding restructuring/rehabilitation of sick small enterprises.

Statement I

State and UT-wise number of registered units as on 31 December 2005

Sl. No.	Name of the State/Union territory	No. of registered SSI Units
1	2	3
	State-wise break-up	
01.	Jammu & Kashmir	19348
02.	Himachal Pradesh	13084
03.	Punjab	68798
04.	Uttaranchal	21757
05.	Haryana	41125
06.	Rajasthan	60657
07.	Uttar Pradesh	259401
08.	Bihar	70506
09.	Sikkim	235
10.	Arunachal Pradesh	416
11.	Nagaland	3339
12.	Manipur	5024
13.	Mizoram	3954
14.	Tripura	973
15.	Meghalaya	3602

1	2	3
16.	Assam	21414
17.	West Bengal	47542
18.	Jharkhand	25015
19.	Orissa	15134
20.	Chhattisgarh	39821
21.	Madhya Pradesh	135769
22.	Gujarat	186057
23.	Maharashtra	115994
24.	Andhra Pradesh	69888
25.	Karnataka	149405
26.	Goa	3026
27.	Kerala	148664
28.	Tamil Nadu	295136
	UNION TERRITORY-WISE BREAK UP	
01.	Chandigarh	1494
02.	Delhi	7654
03.	Daman & Diu	1866
04.	Dadra & Nagar Haveli	1479
05.	Lakshadweep	117
06.	Pondicherry	2484
07.	Andaman & Nicobar	1079
	ALL INDIA TOTAL:	**1841248**

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, in my first supplementary I would like to know from the hon. Minister, through you, whether it is a fact that due to liberalisation of policies of the previous Government, which are still continuing during the present Government also, the industrial commodities are ushering in at the Indian markets in unrestricted quantities. Moreover, as the exporting countries provide subsidies, these commodities are being sold at a cheaper rate. That is why the commodities coming out of the small scale industries of the country cannot compete with them, both in quality and in the rate of prices. Is it not true that the small scale industries are withering away for these reasons and what steps the Government is proposing to take?

श्री महावीर प्रसाद: श्रीमन्, माननीय सदस्य का कहना है कि उदारीकरण के आधार पर लघु उद्योग पर कुप्रभाव पड़ता है, अत: मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि

सरकार इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय कर रही है। उदारीकरण के आधार पर ऐसे प्रतिस्पर्द्धात्मक उपाय किए जा रहे हैं, जिनसे हम विश्व बाजार में अन्य उद्योगों से मुकाबला कर सकें। इसके लिए हमने बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि लघु उद्योगों के लिए हमने क्रैडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता दी जाती है ताकि यदि विदेशों से कोई माल आ रहा है तो हम मुकाबला कर सकें। इसके लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ लघु उद्योग के स्तर में बढ़ोतरी करके गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है और उसी गुणवत्ता के आधार पर हम यह चाहते हैं कि हमारा लघु उद्योग विश्व बाजार में मुकाबला करने के लिए तैयार हो सके और हम तैयार भी हैं। हमारे लघु उद्योग दिन-प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे उद्योग जगत में आज लघु उद्योग की हिस्सेदारी 39% है। इसी प्रकार से निर्यात में लघु उद्योग की हिस्सेदारी 34% है।

श्रीमन्, इस तरह से उद्योग जगत में प्रतिस्पर्द्धा के साथ लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार विचार कर रही है। लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो माननीय सदस्य का प्रश्न मूलतः राज्य सरकारों के लिए है। लघु उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय सरकार केवल संवर्धन संबंधी...(व्यवधान)

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, it is amazing. Thirty-nine per cent of the small scale industries have been closed. It is not a small number. Out of 22 lakhs, though here the Minister has written 18 lakhs, but the same question I placed in this House in the month of May. It was more than 22 lakhs registered as small industries. About nine lakhs have been closed. That is about 39 per cent. I have asked the hon. Minister how many workers have been rendered jobless. The hon. Minister did not reply to me. My specific question is: will the Government provide support to these small scale industries, specifically to these small scale industries, by obtaining for them better market facilities and other necessary assistance so that the large number of artisans and marketers involved in this sector are not rendered jobless and those who are rendered jobless; maybe provided with suitable jobs in the small scale industries?

श्री महावीर प्रसादः हां, केन्द्रीय सरकार उसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो ऐसे जितने भी कार्यक्रम हैं, उनकी जानकारी हम उन्हें लिखित में भेज देंगे। उपसभापति महोदय, केन्द्र स्तर पर इस प्रकार की कोई गणना नहीं की जाती है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे दो कार्यक्रम हैं-लघु उद्योग में और एआरआई में। कृषि लघु उद्योग में आरईजीपी, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और पीएमआरवाई, प्रधान मंत्री रोजगार कार्यक्रम है। ..(व्यवधान)...यदि हमारे मंत्रालय को पता चलता है, तो उनको उसमें समाहित

करने के लिए–यदि वे शर्त पूरी करते हैं, बैंकिंग का और सबका पूरा करते हैं–तो हम कोशिश करते हैं कि उनको उन उद्योगों में प्राथमिकता के आधार पर स्थान दें।

श्री राम नारायण साहू: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बंद हुई इकाइयों पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय संस्थाओं का कुल कितना पैसा बर्बाद हुआ और उसकी जवाबदेही क्यों नहीं सुनिश्चित की गई?

श्री महावीर प्रसाद: उपसभापति महोदय, कितना पैसा बर्बाद हुआ, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य विशेष रूप से इस प्रकार की कोई सूचना चाहते हैं, तो मैं उनको सूचित कर दूंगा।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मुझे मंत्री जी के जवाब से बड़ा अफसोस है। सर, यह सही नहीं है यहां पर अगर कोई सवाल होता है, तो उसका जवाब भी ठीक तरह से होना चाहिए। अब आप जवाब देखिये, इसमें 2003 के बाद कोई फिगर नहीं है। जब आप वर्ष 2003 तक की फिगर रख सकते हैं, तो आपके पास उसके बाद की फिगर क्यों नहीं हैं? क्या स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रॉविजन्स रखते हैं और उसके बाद जॉबलैस को नौकरी देने के लिए प्रॉविजन्स रखते हैं, तो जो आपके मंत्रालय से संबंधित सवाल है, उसका जवाब तो ठीक तरह से दें। आज के समय में 39 परसेंट इंडस्ट्री बंद होना बहुत मायने रखती है। नम्बर दो, आजकल जो माल चाइना से आ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी स्माल स्केल इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने सेंट्रल लेवल पर कोई कमेटी बनाई है, जो यह देखे कि उन लोगों का कितना नुकसान हो रहा है? लोगों ने और आपने पढ़ा होगा कि कई लोगों ने खुदकुशी की है, उन्होंने इस वजह से सुसाइड किया है कि वे बैंकों का और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्युशन्स का पैसा नहीं दे पाये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को सीरियसली लेंगे और इसके लिए कोई कमेटी बनाकर यह देखेंगे कि कितना नुकसान लोगों का हो रहा है और कैसे स्माल स्केल यूनिट्स को रिवाइव किया जाये?

श्री महावीर प्रसाद: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य इस प्रश्न को जितनी गंभीरता से ले रहे हैं, उतनी ही गंभीरता से मैं भी ले रहा हूं। माननीय सदस्य हमारे पुराने मित्र हैं और दिल्ली के विद्वान हैं। लघु उद्योगों के विषय में, कमेटी बनाने के बारे में जब वह बात करना चाहते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार की गणना का कोई प्रावधान नहीं है। हां, जब रुग्णता की बात आती है, तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया के आधार पर, वाणिज्यिक बैंकों से हम रिपोर्ट लेते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर हम यह कहते हैं कि कितनी हमारी यूनिट्स रुग्ण हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उप-गवर्नर के अधिकार में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, जो बारबार इसकी समीक्षा करती है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो समीक्षा करने के अलावा, हम देखेंगे कि यदि और कोई कमेटी बनाने की जरूरत होगी, तो हम उस पर विचार करेंगे।

SHRI S.G. INDIRA: Sir, after de-reservation of many items from the List of SSI, the units which are producing de-reserved items, have become non-viable. Accordingly, this led to the closure of many SSI units. The entry of multinational and larger industries in the production of reserved items made the small-scale industries uncompetitive. So, I would like to know from the hon. Minister what steps the Government is going to take to help the small-scale industries in this regard. I would also like to know whether any special items have been reserved for SSI sector. If yes, the details may be given.

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत उचित है।...(व्यवधान).. यह तो आपकी राय से है।

श्री उपसभापति: ठीक है। आप बोलिए। आप उनकी बात मत सुनिए।

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, आरक्षण-अनारक्षण करने की एक विधि है, प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पर जितने स्टेक होल्डर होते हैं, उद्योग संघ होते हैं, उनसे राय ली जाती है। जितने संबंधित मंत्रालय हैं, उनसे राय ली जाती है, विशेषज्ञों से राय लेते हैं और उसके बाद आईडीआर एक्ट 1951 के आधार पर एक सलाहकार समिति बनी हुई है, उस समिति के परामर्श से किसी मद को हम आरक्षित से अनारक्षित करते हैं। महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्या को मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से अनारक्षण से लघु उद्योग में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि मेसर्ज दलाल कंसलटेंट एक संगठन है, जिसके आधार पर 15 मदों का हमने मूल्यांकन करवाया। उन 15 मदों में से 14 मदों को छोड़कर बिस्कुट एक मद है, जिसमें सीमांत कुछ कमी आयी है और इस प्रकार से अनारक्षण करने से, यह कहना गलत है कि हमारे लघु उद्योग मर रहे हैं। हम सतर्क और सचेत हैं। लघु उद्योगों को जीवित रखने के लिए विश्व मार्किट में प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए सरकार सचेत है और उसके प्रति हम काम कर रहे हैं।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, the answer says that about 39 per cent industries have been closed down because of the three main reasons-Lack of working capital; lack of raw material; and inadequate electricity supply. In view of the reasons given by him, I would like to know from the hon. Minister what steps are being contemplated by his Ministry in this regard. The second part of my question is this. After the revival package, after the credit package given during 2005, how many sick industries have revived? Lastly, Sir, as my colleague has mentioned, and I had also raised this issue on a number of occasions, earlier we used to have small units for producing mineral water, but, now big industries and mult-national industries have entered in this field. As a result, many small

industries have disappeared. Even today, despite the huge losses incurred by the small industries, the Department is registering big industries that intend to produce mineral water. What action has been taken in this regard?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The first part of your questions has been answered.

श्री महावीर प्रसाद: श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, बिजली, पानी आदि कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनका उत्तर मैं पहले ही प्रश्न का उत्तर देते समय बता चुका हूं.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The first part of your question has been answered.

श्री महावीर प्रसाद: कि इनका संबंध राज्य सरकारों से है। मैं आपसे कहूंगा कि इसमें आप भी मेरी मदद करिए। बिजली की व्यवस्था राज्य सरकार करती है, सुरक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करती है, आवागमन की व्यवस्था राज्य सरकार करती है और इस प्रकार से जो संरचना का कार्य है, इनफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसे राज्य सरकार करती है और केन्द्र सरकार पूरक के रूप में काम करती है। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न के प्रति सचेत होकर काम करें।

Bamboo as a source of sustainable livelihood in rural sector

*204. SHRI B. J. PANDA:
MRS. PRAMILA BOHIDAR:††

Will the Minister of AGRO AND RURAL INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bamboo is a source of sustainable livelihood in the rural sector and Orissa has great potential in this sector;

(b) whether Government propose to help and encourage the case-strapped backward State of Orissa to boost its growth to improve the rural economy of the State; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRO AND RURAL INDSUTRIES (SHRI MAHAVIR PRASAD): (a) to (c) Necessary approval to start implementation of the proposed "National Bamboo Mission" prepared by the Ministry of Agriculture, Government of India for its implementation throughout the country, including Orissa, has not been received. However, the Ministry of Environment and Forests, Government of India has advised all State Governments, including

††The question was actually asked on the floor of the House by Ms. Pramila Bohidar.